भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 86*

दिनांक 22.11.2016/01 अग्रहायण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कार्य-योजना

***86. श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सलवाद से प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है एवं उस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;
(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान नक्सलियों को रोकने/खत्म करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और वर्ष-वार और राज्य-वार उसका कितना उपयोग किया गया; और
(ङ) नक्सल प्रभावित जिलों में संपूर्ण सुधार करने एवं उनके विकास के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 22.11.2016 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): दस राज्यों के 106 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित समझे जाते हैं। इन जिलों की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) से (ड.): वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों अधिकारों और हकदारियों से संबंधित उपाय सुनिश्चित करने आदि को सम्मिलित करते हुए एक एकीकृत बहुआयामी रणनीति शामिल है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार अलग-अलग केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास/प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता पहुंचाती है। अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के अतिरिक्त, कुछ प्रमुख विकास संबंधी योजनाओं में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सड़क सम्पर्क में सुधार हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सड़क आवश्यकता योजना – 1, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सम्पर्क में सुधार हेतु दूर संचार विभाग के माध्यम से मोबाइल टॉवरों की स्थापना शामिल है।

.....3/-

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के नाते वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से निपटने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, गृह मंत्रालय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती तथा सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, अतिसुरक्षित और सशक्त (फोर्टीफाइड) पुलिस थाना योजना, विशेष अवंसरचना योजना, नागरिक कार्य योजना और मीडिया योजना के माध्यम से सहायता के द्वारा राज्य सरकारों के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में सहायता करती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि और उनके उपयोग का का ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 22.11.2016 के लिए लोक सभा ता० प्र० सं० 86

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के 106 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	8	अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कुरनूल, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम एवं विजियानगरम ।
2.	बिहार	22	अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पश्चिम चंपारन, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारन, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगूसराय एवं खगड़िया ।
3.	छत्तीसगढ़	16	बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया (बैकुंठपुर), नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलोद, सुकमा, कोंडागांव एवं बलरामपुर ।
4.	झारखंड	21	बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लाटेहर, लोहारडग्गा, पलामू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसवान, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, दुमका, देवघर एवं पाकुर ।
5.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट
6.	महाराष्ट्र	4	चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया एवं अहेरी ।
7.	ओडिशा	19	गजपति, गंजम, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरि मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कोंधमाल, देवघर, जयपुर, धेनकनाल, कालाहांडी, नौपाड़ा, बरगढ़ एवं बोलनगीर ।
8.	तेलंगाना	8	अदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, मेदक, महबूबनगर, नलगोंडा, वारंगल एवं निजामाबाद ।
9.	उत्तर प्रदेश	3	चंदौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र ।
10.	पश्चिम बंगाल	4	बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया एवं बीरभूम ।
कुल		106	

*****

अनुलग्नक-।। का पृष्ठ-।

दिनांक 22.11.2016 के लिए लोक सभा ता० प्र० सं० 86

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत जारी की गई धनराशि

(आंकड़े लाख रूपए में)

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिनांक15.11.16 की स्थिति के अनुसार)
आन्ध्र प्रदेश	1798.02	1202.21	1254.50	677.98
बिहार	1710.89	1898.79	1799.40	658.37
छत्तीसगढ़	4214.41	4179.51	7310.92	2575.48
झारखंड	4778.74	4801.23	5933.16	3025.95
मध्य प्रदेश	55.75	140.07	150.82	-
महाराष्ट्र	738.51	1758.21	1885.97	1100.30
ओडिशा	4813.30	4624.69	5035.27	1355.31
तेलंगाना	-	509.56	743.04	520.84
उत्तर प्रदेश	533.28	316.02	395.91	231.56
पश्चिम बंगाल	2065.10	1277.71	1356.01	1003.23
कुल	20708.00	20708.00	25865.00	11149.02

नोट: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय, जैसे वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए आम नागरिक/सुरक्षा कार्मिक के परिवार को अनुग्रह भुगतान, पुलिस कार्मिकों का बीमा, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण एवं प्रचालन संबंधी आवश्यकताएं, संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजा, समुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसरंचना आदि के लिए एक प्रतिपूर्ति आधारित योजना है।

अनुलग्नक-।। का पृष्ठ-2

दिनांक 22.11.2016 के लिए लोक सभा ता० प्र० सं० 86

विशेष अवंसरचना योजना (एसआईएस) के तहत जारी की गई धनराशि

क्रम सं.	राज्य	जारी निधियां (करोड़ रूपए में)				प्रयोग की गई निधियां (करोड़ रूपए में)
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
1	आन्ध्र प्रदेश	9.99	7.00	इस योजना को केन्द्रीय सहायता से विलग कर दिया गया। इस योजना का उपयोग अवसंरचना, प्रशिक्षण, हथियार, उपकरण और वाहनों के उन्नयन के वित्त पोषण हेतु किया जाना था।		9.99
2	बिहार	15.06	4.04			15.06
3	छत्तीसगढ़	16.34	16.55			0.96
4	झारखंड	16.52	-			15.24
5	ओडिशा	16.22	17.41			30.85
6	तेलंगाना	-	3.00			3.00
	कुल	74.13	48.00			75.10

नागरिक कार्य योजना (सीएपी) के अंतर्गत जारी की गई राशि					
इसमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न नागरिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है।	जारी निधियां (करोड़ रूपए में)				प्रयोग की गई निधियां (करोड़ रूपए में)
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
	15.74	17.65	19.02	19.00	49.09

मीडिया योजना के तहत जारी की गई धनराशि

इसमें सरकार की विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने हेतु एजेंसियों को निधियां प्रदान की जाती है।	जारी राशि (करोड़ रुपए में)				प्रयुक्त राशि (करोड़ रुपए में)
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
	5.00	5.00	3.50	2.65	N/A

*****